ई संदेश

11 जून, 2026 | अंक - 209

सात दिन, सात पृष्ठ

- पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया प्रकृति और जीव सृष्टि के संरक्षण का संदेश
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 294 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास
- रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम तथा परिणामोन्मुख बनाया जाए
- गोण्डा के कटरा बाजार और कर्नलगंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी 516 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
- मौसम की सटीक जानकारी से देश का खाद्यान्न उत्पादन 36 प्रतिशत तक बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है उत्तर प्रदेश
- वस्त्र और माटीकला उद्योग से युवाओं तथा कारीगरों को बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार: मुख्यमंत्री
- अग्निशमन विभाग में बनेगा 'विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप', सुरक्षा तंत्र होगा और अधिक मजबूत: मुख्यमंत्री
- 'प्रोजेक्ट गंगा' से गांवों में पहुंचेगी हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा और महिलाएं
- सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
- आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाएं : मुख्यमंत्री
- प्रधानमंत्री जी के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री जी ने दीं शुभकामनाएं

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया प्रकृति और जीव सृष्टि के संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 जून, 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम की विशिष्ट प्रजाति 'अरुणिका' का पौधरोपण करके प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण महाभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रदेशवासियों को पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से विगत 09 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में सरकार के गठन के समय वन महोत्सव के अवसर पर 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया था, जो उस समय नर्सरी और अनुभव की कमी के कारण एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने गौरव के साथ यह बात रेखांकित की कि विगत 09 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के तहत रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण कर अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है, जिससे राज्य के फॉरेस्ट कवर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता स्वरूप शुरू किए गए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की सराहना करते हुए इसे उत्तर प्रदेश में एक व्यापक जनांदोलन का रूप दिया।

मुख्यमंत्री जी ने श्रीराम के अमर उद्घोष 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का स्मरण कराते हुए कहा कि जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मौसम चक्र में बदलाव और जैव प्रजातियों के संकट जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए ही राज्य सरकार व्यापक स्तर पर यह पौधारोपण अभियान चला रही है।

मुख्यमंत्री जी ने सरकार के अन्य प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित किया गया है और इसके स्थान पर माटी कला बोर्ड के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों द्वारा बड़े आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने अंत में इस बात पर विशेष बल दिया कि यदि पर्यावरण बचेगा, तभी प्रकृति और जीव सृष्टि की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें ध्यान रखना होगा पर्यावरण बचेगा, तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी, तो जीव सृष्टि भी बचेगी। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। 'एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महाभियान' उसी श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' का शुभारम्भ करते उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 294 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 जून, 2026 को जनपद बलरामपुर में 294 करोड़ रुपये लागत की 75 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रतीकात्मक चेक तथा आवास की चाबियां प्रदान कीं। इससे पूर्व, उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन किया और कार्यक्रम स्थल पर हरिशंकरी का पौधरोपण करने के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने डबल स्पीड से कार्य करके बलरामपुर को विकसित जनपद बनने की ओर तेजी से अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि जनपद में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना साकार हो चुकी है, साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज तथा माँ पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। थारू जनजाति के गौरव को जीवंत रखने के लिए इमलिया कोडर में थारू संग्रहालय की स्थापना की जा चुकी है और राप्ती नदी के मथुरा घाट पर पुल के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क राशन, आवास, शौचालय और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर का लाभ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बलरामपुर जनपद वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सबसे अधिक बच्चों का नामांकन कराने वाला जिला बन चुका है, जो विकास प्रक्रिया का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करता है। सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को सुरक्षा, सुशासन और रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था और राज्य की बदलती छवि को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के समक्ष पहचान का जो संकट था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बड़े निवेश, उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, बेहतरीन कनेक्टिविटी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों से होती है। उन्होंने कहा कि माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के साथ-साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम और माँ पाटेश्वरी धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार से प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक नई और गौरवशाली पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण और भविष्य के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे पी0एल0ए0 (बायो-प्लास्टिक) प्लांट की सराहना की, जो पर्यावरण के अनुकूल है और बहुत जल्द मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाता है। उन्होंने समूह से बलरामपुर में एक औद्योगिक पार्क बनाने का आह्वान किया ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने अंत में इस बात पर विशेष बल दिया कि 'जल है तो कल है और वन है तो जीवन है', इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों और जल प्रदूषण को रोकना पूरी मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम तथा परिणामोन्मुख बनाया जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 जून, 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम तथा परिणामोन्मुख बनाए जाने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल यातायात वाला राज्य है, जहाँ प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे नेटवर्क में अपराध और असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए तथा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने रेलवे परिसरों, प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने रेलवे परिसरों और ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। भीड़ प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों, बड़े आयोजनों, भर्ती परीक्षाओं और विशेष अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रवेश एवं निकास नियंत्रण, कतार प्रबन्धन और 24 घण्टे सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से भीड़ नियंत्रण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए रेलवे नेटवर्क में महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए चल रहे अभियानों को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, जिसके तहत 'ऑपरेशन मुस्कान' के शानदार प्रयासों की भी सराहना की गई।

मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दण्ड सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने जीआरपी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग देने की बात कही। इसके साथ ही, वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार अर्धकुम्भ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अभी से ही व्यापक सुरक्षा एवं भीड़ प्रबन्धन योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

गोण्डा के कटरा बाजार और कर्नलगंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी 516 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

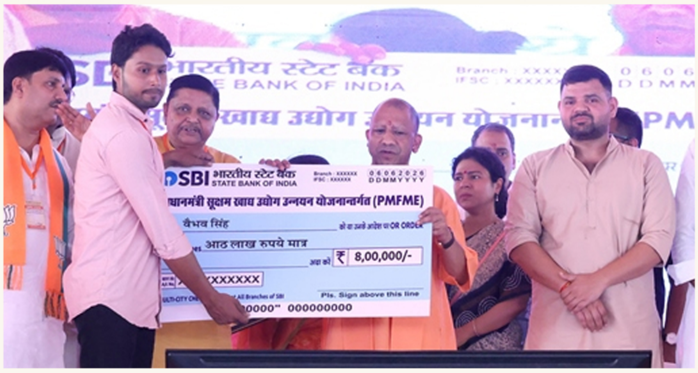

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 जून, 2026 को जनपद गोण्डा के कटरा बाजार और कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए 516 करोड़ रुपये की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबियां, स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के सफल नेतृत्व और राज्य की डबल इंजन सरकार के 09 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिली है, जिसके परिणामस्वरूप अब गोण्डा के युवाओं को पहचान के संकट से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के भाई-भतीजावाद के कारण इस पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था, लेकिन वर्तमान में सरकार की निष्पक्ष नीतियों से गोण्डा और उसके आस-पास के जनपदों का तेजी से कायाकल्प हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुई 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती में गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के सैकड़ों युवाओं का चयन हुआ है। अब निवेश केवल कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गोण्डा में भी नए उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 से पूर्व पर्वों और त्योहारों पर जो कर्फ्यू लग जाता था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और यदि किसी ने भी उत्सव के रंग में भंग डालने का प्रयास किया, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक और सामाजिक गौरव की चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के दृढ़ संकल्प से 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर निर्मित हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र की महिमा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि गोण्डा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने के कारण ही संभव हो सका है। इसके अतिरिक्त, श्रावस्ती में बन रहे नए एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव के ऐतिहासिक शौर्य का स्मरण कराते हुए उन्होंने इसे पूरे क्षेत्र के विकास का एक बड़ा आधार बताया।

मुख्यमंत्री जी ने भविष्य की योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि 05 जून से 21 जून तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने गोण्डा में बढ़ रहे प्राकृतिक खेती के दायरे तथा 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत घर-घर सोलर पैनल लगाने की पहल की सराहना की, जिससे ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने अंत में मटियारी घाट पर दीर्घ सेतु निर्माण, घाघरा नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम और टेढ़ी नदी पर लंबित पुल निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करते हुए कहा कि इन कदमों से हजारों एकड़ कृषि भूमि सुरक्षित होगी और युवाओं के लिए प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे।

मौसम की सटीक जानकारी से देश का खाद्यान्न उत्पादन 36 प्रतिशत तक बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 जून, 2026 को मिशन मौसम के अन्तर्गत मौसम विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के 'क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र' के रूप में उन्नयन की घोषणा होने के उपरांत आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सहित भारत मौसम विज्ञान विभाग की टीम को धन्यवाद देते हुए इसे विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ प्रचुर जल संसाधन और अत्यधिक उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। इस प्राकृतिक संपदा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय पर सटीक जानकारी मिलने से अन्नदाता किसानों की फसलों को होने वाली क्षति, अर्थव्यवस्था के नुकसान तथा संभावित खाद्यान्न संकट को काफी हद तक रोकने में सफलता मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की कि क्लाइमेट चेंज के कारण संपूर्ण मौसम चक्र में लगभग एक महीने का अंतर आ गया है, जिससे भविष्य में दुनिया के सामने खाद्यान्न संकट आ सकता है। उन्होंने बल दिया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, का व्यवहार रखना होगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सहारनपुर के माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर क्षेत्र में भारी बारिश और मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली में आकाशीय बिजली की आपदा के दौरान समय पर सटीक अलर्ट मिलने से जन-धन की व्यापक हानि को रोका गया।

मुख्यमंत्री जी ने राज्य में मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2,000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जो आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की रीयल-टाइम निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 86 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है और यदि किसानों को मौसम की बिल्कुल सही जानकारी मिलती रहे, तो प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में अपने योगदान को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 से 36 प्रतिशत करने का सामर्थ्य रखता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अनेक वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें पूरा सहयोग मिलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या, उपजाऊ भूमि और जलवायु विविधता को देखते हुए यहाँ आईएमडी का क्षेत्रीय सेंटर होना अत्यंत आवश्यक था। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 01 डॉप्लर वेदर रडार था, जबकि वर्तमान में यहाँ 03 रडार सक्रिय हैं और 06 अन्य रडार लगने वाले हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी 59 से बढ़कर 107 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में स्थापित हो रहा यह नया रीजनल सेंटर उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र को भी संभालेगा, जिससे कृषि, विमानन और जलवायु शोध को भारी बढ़ावा मिलेगा।

वस्त्र और माटीकला उद्योग से युवाओं तथा कारीगरों को बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 जून, 2026 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप एक व्यापक कौशल विकास कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्योगों को समय पर पूरी तरह प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों का मूल लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित न होकर युवाओं को सीधे रोजगार और स्थायी आजीविका से जोड़ना होना चाहिए। वस्त्र क्षेत्र में अत्यंत तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों, ऑटोमेशन और आधुनिक मशीनरी के विस्तार को देखते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरी तरह समयानुकूल बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वस्त्र उद्योगों की वास्तविक जरूरतों का सही आकलन करते हुए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी और शत-प्रतिशत रोजगारपरक बनाया जाए।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राज्य में 'समर्थ योजना' के माध्यम से अब तक 2.28 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 1.60 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न रोजगारों से जोड़ा गया है। इस पूरे अभियान में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से अद्वितीय रही है, जिनका कुल प्रशिक्षणार्थियों में हिस्सा 87 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से भी युवाओं को वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न ट्रेड्स में लगातार उन्नत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने माटीकला क्षेत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सेक्टर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मिट्टी से निर्मित उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कारीगर परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार हैं। उन्होंने पर्यावरण मित्र माटीकला उत्पादों के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के साथ ही कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, सोलर चाक, नई तकनीक, बेहतर उपकरण, वित्तीय सहायता और प्रभावी विपणन सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार पर बल देते हुए कहा कि इन उद्योगों को केवल संरक्षण की ही नहीं, बल्कि नवाचार, ब्रांडिंग, डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बाजार से जुड़ाव की सख्त आवश्यकता है। माटीकला के उत्कृष्ट उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वैश्विक डिजाइन विकास और आधुनिक विपणन प्रणालियों से जोड़कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने संबंधित विभागों को एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर बैंकों से बेहतर समन्वय बनाने, वित्तीय सहायता सुलभ कराने और रोजगार सृजन की पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

अग्निशमन विभाग में बनेगा 'विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप', सुरक्षा तंत्र होगा और अधिक मजबूत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 जून, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेष आपात परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्य में जल्द ही एक नई विशेषज्ञ टीम 'विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप' (एस0आर0जी0) के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बदलते आपदा परिदृश्य और नई चुनौतियों को देखते हुए पहले चरण में 10 जनपदों में एस0आर0जी0 की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके तहत 240 कर्मियों को एन0डी0आर0एफ0, बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0 और सी0आई0एस0एफ0 जैसे विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी, औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा व्यवस्था को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत किया जाना आवश्यक है। अब यह विभाग केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, सम्पत्ति, उद्योगों और निवेश की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। भवन ध्वस्त होने, बाढ़, रासायनिक दुर्घटनाओं, ऊँचाई पर फँसे लोगों के रेस्क्यू और संकरे स्थानों में बचाव जैसे जटिल अभियानों में यह टीम आधुनिक उपकरणों के साथ त्वरित कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही बहुमंजिला इमारतों ने अग्निसुरक्षा की नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। इन हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 में 102 मीटर क्षमता के 10 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, 90 मीटर क्षमता के 03 तथा 72 मीटर क्षमता के 07 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना है। इसके अतिरिक्त, 100 मंजिल तक प्रभावी अग्निशमन क्षमता वाले आधुनिक तकनीक से लैस 14 विशेष फायर फाइटिंग वाहनों की खरीद भी प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट कराने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फसलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 के बाद से विभाग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रदेश में अग्निशमन केन्द्रों की संख्या 140 से बढ़कर 260 हो गई है, जबकि फायर वाहनों की संख्या 750 से बढ़कर 1,660 हो चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने निवेश और उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फायर एन0ओ0सी0 व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि फायर सर्विस पोर्टल को निवेश मित्र 3.0 से एकीकृत किया जा चुका है और एन0ओ0सी0 की वैधता अवधि को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी ब्लॉकों में अग्निसचेतक तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और आगामी चरण में स्वयंसेवकों के लिए समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप विकसित करके सिविल डिफेंस, होमगार्ड और पी0आर0डी0 जैसी इकाइयों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

'प्रोजेक्ट गंगा' से गांवों में पहुंचेगी हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा और महिलाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 जून, 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से अभिनव पहल 'प्रोजेक्ट गंगा' का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में डिजिटल उद्यमिता के इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदूजा ग्रुप के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रॉडबैंड वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इंटरनेट की गति जितनी तेज होगी, राज्य के विकास की रफ्तार भी उतनी ही तीव्र होगी, जिससे ग्रामीणों के जीवन में व्यापक और सकारात्मक बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित डिजिटल सशक्तिकरण के लक्ष्य के अनुरूप इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में 08 हजार डिजिटल उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि हिंदूजा ग्रुप गांवों में लास्टमाइल तक डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल एंटरप्रेन्योर सुगमता से कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' जैसी वित्तीय समावेशन की योजनाएं युवाओं को 05 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान कर इस मॉडल को और मजबूत करेंगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले चरण में 'प्रोजेक्ट गंगा' के तहत प्रदेश के 21 जनपदों का चयन किया गया है, जिसे शीघ्र ही सभी 75 जनपदों की 350 तहसीलों, 825 विकास खंडों और 8,000 न्याय पंचायतों तक विस्तारित करते हुए अंततः 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने नीति आयोग द्वारा सराहे गए उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालय मॉडल की चर्चा करते हुए कहा कि ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलने से ये सचिवालय 'स्मार्ट विलेज' के रूप में विकसित हो सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री जी ने विकास के एक सस्टेनेबल मॉडल पर बल देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए और सरकार पर उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। उन्होंने इस बात की आवश्यकता जताई कि 'प्रोजेक्ट गंगा' से जुड़ने वाली महिला उद्यमियों की 'बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सखी' की तर्ज पर एक विशेष यूनिफॉर्म और विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, साथ ही उनके कार्यों में विभिन्न आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलोज के अनुभवों का भी पूरा लाभ लिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा ने 'प्रोजेक्ट गंगा' को डिजिटल क्रांति का आधार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के डिजिटल विकास का मुख्य ग्रोथ इंजन बन चुका है। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह और हिंदूजा ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ कर शहर और गांव के बीच के डिजिटल डिवाइड को पूरी तरह समाप्त कर देगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 जून, 2026 को सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योगों और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है, जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके।

मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इस परियोजना को केवल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित ईको-सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए ही इस सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की माँग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

इस समीक्षा बैठक में 09 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब एवं स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केन्द्र (हब) तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केन्द्र (स्पोक) विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्लेसमेण्ट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केन्द्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कौशल विकास केन्द्र, औद्योगिक भूखण्ड, प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक सुविधाएँ, साझा सुविधा केन्द्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएँ, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएँ एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी।

परियोजना के प्रथम चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है, जबकि अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इसके तहत प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान (जॉब मैचिंग) का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80 प्रतिशत प्लेसमेण्ट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 02 लाख से अधिक नए एम0एस0एम0ई0 उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गिग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस परियोजना में सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (आई0टी0ई0) और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था आई0टी0ई0ई0एस0 के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। यह संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास और प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा क्रियान्वयन मॉडल से सम्बन्धित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए इस पूरी परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।

आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 जून, 2026 को एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एकरूप बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने इसके माध्यम से आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं और मानदेय व्यवस्था में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हो और विभागों को भी सुव्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मियों से सम्बन्धित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास कार्य की समीक्षा करते हुए इसे समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति, सत्यापन, अनुश्रवण तथा अन्य प्रक्रियाओं का केन्द्रीकृत संचालन किया जाए, जिससे व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सके।

बैठक में आउटसोर्स एजेंसियों के एम्पैनलमेण्ट की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एजेंसियों के चयन एवं संचालन से सम्बन्धित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट, मानकीकृत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए तैयार की जा रही व्यवस्था को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए, ताकि सभी विभागों को एक समान और सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रसेवा, सुशासन एवं जनकल्याण को समर्पित 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 जून, 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के राष्ट्रसेवा, सुशासन एवं जनकल्याण को समर्पित 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर पत्र लिखकर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें अनन्त शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री जी को प्रेषित पत्र में मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि उनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व एवं सतत मार्गदर्शन में 'विकसित भारत' के संकल्प के अनुरूप 'विकसित उत्तर प्रदेश' के निर्माण हेतु पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा तथा राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देता रहेगा।

मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में लिखा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीरामलला का विराजमान होना और श्री काशी विश्वनाथ धाम के सफल पुनरोद्धार के साथ ही 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र ने भारत के विकास को नई दिशा, नई गति और नया विश्वास प्रदान किया है। राष्ट्र ने सेवा, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी जनकल्याण, सुशासन और समावेशी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों तक पहुँचा है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 03 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगभग 65 लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लगभग 10 करोड़ पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिली। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के 03 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा अन्य किसान हितैषी कार्यक्रमों ने कृषि उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। मिशन रोजगार के अन्तर्गत 09 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई। वहीं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 25 लाख युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्लेसमेण्ट उपलब्ध कराए गए। निवेश आधारित औद्योगिक विकास, एम0एस0एम0ई0, ओ0डी0ओ0पी0, स्टार्टअप तथा स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 03 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए, जिससे युवा शक्ति प्रदेश की विकास यात्रा की प्रमुख भागीदार बनी।

मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में प्रदेश में हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास की चर्चा करते हुए उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आधुनिक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। दिल्ली-मेरठ 12-लेन एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ नमो भारत (आर0आर0टी0एस0), देश का प्रथम इनलैण्ड वाटर-वे, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वंदे भारत एवं नमो भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। आज उत्तर प्रदेश अपनी विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे श्रृंखला के कारण देशभर में 'एक्सप्रेस-वे प्रदेश' के रूप में स्थापित हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन, आधुनिक हवाई अड्डों, मेट्रो परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तथा औद्योगिक कॉरिडोर के विकास ने निवेश, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई दी है।

मुख्यमंत्री जी ने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई है। आज प्रदेश माफिया-मुक्त, दंगा-मुक्त और भयमुक्त वातावरण की पहचान बना चुका है। व्यापारी, निवेशक, उद्योगपति तथा मातृशक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश-अनुकूल वातावरण ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में स्थापित किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2017 की तुलना में लगभग तीन गुना हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है तथा बेरोजगारी दर लगभग 18 प्रतिशत से घटकर लगभग 03 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। उत्तर प्रदेश आज वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है तथा 'विकसित भारत' के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित